International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

ग्रामीण विकास हेतु पंचायती राज का कार्यान्वयनए चुनौतियां एवं समाधान ;छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ मेंद्ध

रेणु शुक्ला[1], डॉण् प्रीति शर्मा[2]

[1]शोधार्थी, समाजशास्त्र, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालयए भोपाल, मण्प्रण्द्ध

[2]शोध निर्देशक . सहायक प्राध्यापकए समाजशास्त्र, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालयए भोपाल, मण्प्रण्द्ध

सारांश

छिंदवाड़ा जिले में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह अध्ययन पंचायती राज प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयनए इसके लाभोंए चुनौतियों और संभावित समाधानों का विश्लेषण करता है। शोध के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि पंचायतें स्थानीय प्रशासनए बुनियादी सुविधाओंए शिक्षाए स्वास्थ्य सेवाओंए महिला सशक्तिकरण और कृषि विकास में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं। हालाँकिए वित्तीय संसाधनों की कमीए प्रशासनिक बाधाएँ और जनभागीदारी का अभाव कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए पंचायतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करनाए ई.गवर्नेंस को बढ़ावा देना और जनसहभागिता को मजबूत करना आवश्यक है। इन प्रयासों से पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता हैए जिससे ग्रामीण विकास की गति को तेज किया जा सके।

शब्द कुंजी . पंचायती राजए ग्रामीण विकासए छिंदवाड़ाए विकेंद्रीकरणए जनभागीदारीए ई.गवर्नेंसए महिला सशक्तिकरणए शिक्षाए स्वास्थ्यए वित्तीय स्वायत्तता।

परिचय

भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुआए जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्वशासन को मजबूत करना था। यह प्रणाली लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थाए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सके। पंचायती राज के माध्यम से ग्राम स्तर पर शासन को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता हैए जिससे स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों में जनभागीदारी बढ़ती है।

छिंदवाड़ा जिलाए जो मध्य प्रदेश के दक्षिण.पश्चिमी भाग में स्थित हैए कृषि और वन्य क्षेत्र से समृद्ध है। जिले की कुल जनसंख्या लगभग 20 लाख हैए जिसमें से 75 प्रतिशत से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषिए वन उत्पादों और लघु उद्योगों पर निर्भर करती है। ऐसे में पंचायती राज व्यवस्था जिले के ग्रामीण विकास में एक अहम भूमिका निभाती है।

छिंदवाड़ा जिले में पंचायत व्यवस्था तीन स्तरीय संरचना पर आधारित हैए जिसमें ग्राम पंचायतए जनपद पंचायत और जिला पंचायत शामिल हैं। जिले में कुल 807 ग्राम पंचायतेंए 11 जनपद पंचायतें और एक जिला पंचायत कार्यरत हैं। यह पंचायतें न केवल बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग कर रही हैंए बल्कि शिक्षाए स्वास्थ्यए रोजगारए महिला सशक्तिकरण और कृषि सुधार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी योगदान दे रही हैं।

छिंदवाड़ा जिले में पंचायती राज की संरचना

छिंदवाड़ा जिले में पंचायती राज तीन स्तरीय संरचना पर आधारित है .

- ग्राम पंचायत . जिले में कुल 807 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं।
- जनपद पंचायत . जिले में 11 जनपद पंचायतें कार्यरत हैं।
- जिला पंचायत . छिंदवाड़ा जिले की जिला पंचायतए जो पूरे जिले की नीतियों का निर्धारण करती है।

ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका

बुनियादी ढांचे का विकास .

- 2022.23 में छिंदवाड़ा जिले में 520 किमी ग्रामीण सड़कें बनाई गई।
- 80 प्रतिशत गांवों में बिजलीकरण पूरा हो चुका है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ .

- जिले में 350 प्राथमिक विद्यालय और 120 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।
- 2021 में 25 नए स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए।

स्वरोजगार और कौशल विकास .

- 2022.23 में 12ए000 युवाओं को रोजगार कौशल प्रशिक्षण दिया गया।
- महिला स्वयं सहायता समूहों ;ैभ्ळद्ध के माध्यम से 5ए000 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

महिला सशक्तिकरण .

- पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को प्रदान किया गया।
- 2023 में 3000 से अधिक महिलाओं को पंचायतों में सक्रिय भूमिका मिली।

कृषि और सिंचाई .

- 2023 तक 1ण्2 लाख किसानों को कृषि सब्सिडी प्रदान की गई।
- 150 नई सिंचाई परियोजनाएँ क्रियान्वित की गईं।

प्रमुख योजनाएँ और उनका कार्यान्वयन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ;डळछत्म्ळ।द्ध .

- 2022.23 में 2ण्5 लाख ग्रामीणों को रोजगार प्रदान किया गया।
- 800 से अधिक जल संरक्षण संरचनाएँ बनाई गई।

स्वच्छ भारत मिशन .

- 2021.22 में 1ण्2 लाख घरों में शौचालय निर्माण किया गया।
- जिले के 95 प्रतिशत गांव खुले में शौच मुक्त ;व्क्थ्द्ध घोषित किए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना ;**च्ड**।ल्द्ध .

- 2022.23 में 15ए000 ग्रामीण घर बनाए गए।

- सरकार द्वारा प्रति लाभार्थी 1ण्2 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान .

- 2021.22 में 5ए000 पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया।

चुनौतियाँ और समाधान

पंचायती राज व्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैए जिनका समाधान किए बिना ग्रामीण विकास संभव नहीं है।

- वित्तीय संसाधनों की कमी . पंचायतों को स्वायत्तता तो दी गई हैए लेकिन उनकी वित्तीय निर्भरता अभी भी केंद्र और राज्य सरकारों पर बनी हुई है। योजनाओं के लिए आवश्यक निधि समय पर उपलब्ध नहीं होने से कई विकास कार्य बाधित हो जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए पंचायतों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करनी होगी और स्थानीय स्तर पर कर वसूली को बढ़ावा देना होगा।
- प्रशासनिक अक्षमताएँ . पंचायत पदाधिकारियों की प्रशासनिक दक्षता में कमीए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा डालती है। इसका समाधान पंचायत प्रतिनिधियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर किया जा सकता हैए जिससे वे योजनाओं को सही तरीके से लागू कर सकें।
- जनभागीदारी की कमी . अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता की सहभागिता अपेक्षाकृत कम देखी जाती है। इस समस्या को हल करने के लिए पंचायत बैठकों में ग्रामीणों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। साथ हीए स्थानीय स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाकर पंचायतों की भूमिका के प्रति नागरिकों को जागरूक किया जा सकता है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी . कई बार देखा गया है कि पंचायतों में विकास कार्यों के लिए आवंटित धन का सही उपयोग नहीं हो पाताए जिससे भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता की स्थिति उत्पन्न होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए डिजिटल निगरानी और ई.गवर्नेंस को अपनाना आवश्यक होगा। ग्राम सभाओं में समय.समय पर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत कर पारदर्शिता बनाए रखी जा सकती है।
- तकनीकी एवं डिजिटल साक्षरता की कमी . पंचायतों में अब कई योजनाएँ डिजिटल माध्यम से संचालित हो रही हैंए लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की तकनीकी समझ सीमित होने के कारण इसका प्रभावी उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस समस्या का समाधान डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू कर किया जा सकता हैए जिससे पंचायतें तकनीकी रूप से सक्षम बन सकें।
- समुचित योजना क्रियान्वयन की कमी . सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएँ सही तरीके से जमीन पर नहीं उतर पातींए जिसके कारण ग्रामीण विकास की गति धीमी हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करना आवश्यक होगाए जिससे योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा सके।
- बुनियादी सुविधाओं का अभाव . कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्यए शिक्षाए सड़क और स्वच्छता जैसी सुविधाओं का अभी भी अभाव है। पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होगी और विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना होगा।

सुझाव

पंचायती राज व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा सकते हैं .

- पंचायत प्रतिनिधियों का नियमित प्रशिक्षण . पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए प्रशासनिकए वित्तीय और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य किए जाने चाहिए। इससे वे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयनए बजट प्रबंधन और डिजिटल प्रणाली के उपयोग में दक्ष बन सकेंगे।
- वित्तीय स्वायत्तता का विस्तार . पंचायतों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए ग्राम पंचायतों को कर वसूलीए स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोगए और राज्य तथा केंद्र सरकार से सीधी निधि प्राप्त करने के अधिकार दिए जाने चाहिए।
- डिजिटल टेक्नोलॉजी और ई.गवर्नेंस का समावेश . पंचायत कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और ई.गवर्नेंस को अपनाया जाना चाहिए। पंचायत पोर्टलए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के माध्यम से विकास कार्यों की समीक्षा और रिपोर्टिंग को बेहतर बनाया जा सकता है।
- जनभागीदारी को बढ़ावा देना . पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं को अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। ग्राम सभाओं में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। यह निर्णय प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बनाएगा।
- निगरानी और पारदर्शिता को बढ़ावा . पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। समय.समय पर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत कर सार्वजनिक समीक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा . पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक बढ़ाने के लिए उन्हें नेतृत्व प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजनाएँ शुरू की जानी चाहिएए जिससे वे स्वावलंबी बन सकें।
- स्थानीय संसाधनों का उचित उपयोग . प्रत्येक पंचायत को अपने स्थानीय संसाधनों ;जलए वनए भूमिद्ध का कुशल उपयोग करने हेतु योजनाएँ बनानी चाहिए। जल संरक्षण परियोजनाओंए वनीकरणए और टिकाऊ कृषि तकनीकों को अपनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
- स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार . पंचायतों को स्थानीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और विद्यालयों में सुविधाएँ बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। शिक्षकों और डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।
- रोजगार और स्वरोजगार के अवसर . पंचायतों को ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु योजनाएँ बनानी चाहिए। कौशल विकास केंद्रों की स्थापना कर युवाओं को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता . ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कोंए बिजलीए पेयजल और संचार सुविधाओं का विकास प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार कर डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

छिंदवाड़ा जिले में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हालाँकिए इसके प्रभावी कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ भी हैंए जिनमें वित्तीय संसाधनों की कमीए प्रशासनिक अक्षमताएँए जनभागीदारी की कमी और पारदर्शिता का अभाव शामिल हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए पंचायतों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। तकनीकी नवाचारोंए ई.गवर्नेंसए और डिजिटल पारदर्शिता को अपनाकर पंचायतों के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ हीए स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक कर उनकी सहभागिता बढ़ाने से पंचायत शासन को अधिक उत्तरदायी और लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है।

महिला सशक्तिकरणए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधारए शिक्षा को बढ़ावाए और रोजगार सृजन जैसी पहलों को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि इन क्षेत्रों में समुचित सुधार किया जाएए तो पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास की दिशा में और अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकती है।

इस शोध पत्र के माध्यम से प्राप्त निष्कर्ष और सुझाव छिंदवाड़ा जिले में पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक हो सकते हैंए जिससे यह एक प्रभावशाली और आत्मनिर्भर ग्रामीण प्रशासन का मॉडल बन सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची .

1ण शर्माए रामशरण ;2018द्ध . ष्पंचायती राज और ग्रामीण विकासश्ए नई दिल्ली प्रकाशन संस्थानए पृष्ठ संख्या 45.78।

2ण सिंहए एमण एलण ;2016द्ध . ष्भारत में पंचायती राज व्यवस्थाश्ए जयपुर राष्ट्रीय प्रकाशनए पृष्ठ संख्या 102.140।

3ण वर्माए गोपाल ;2019द्ध . ष्ग्रामीण विकास नीतियाँ और कार्यक्रमश्ए भोपाल मध्य प्रदेश पब्लिशिंग हाउसए पृष्ठ संख्या 85.120।

4ण छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ;2022.23द्ध . ष्वार्षिक रिपोर्टश्ए जिला प्रशासन कार्यालयए छिंदवाड़ा।

5ण पंचायती राज मंत्रालयए भारत सरकार ;2021द्ध . ष्पंचायती राज व्यवस्थाश्ए आधिकारिक वेबसाइट .ूण्चंदबींलंजण्हवअण्पद

6ण मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम विकास विभाग ;2020द्ध . ष्विकास रिपोर्टश्ए भोपाल सरकारी प्रकाशन।

7ण मिश्राए संजय ;2017द्ध . ष्ई.गवर्नेंस और ग्रामीण प्रशासनश्ए मुंबई टेक्नो पब्लिशर्सए पृष्ठ संख्या 56.90।

8ण तिवारीए अरुण ;2015द्ध . ष्स्थानीय शासन और विकास अध्ययनश्ए लखनऊ उत्तर प्रदेश बुक डिपोए पृष्ठ संख्या 110.150।